

## राष्ट्रीय भू-स्थानकि नीति 2022

### प्रलिमिस के लिये:

भू-स्थानकि प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन/रमिट सेंसिं, SDG।

### मेन्स के लिये:

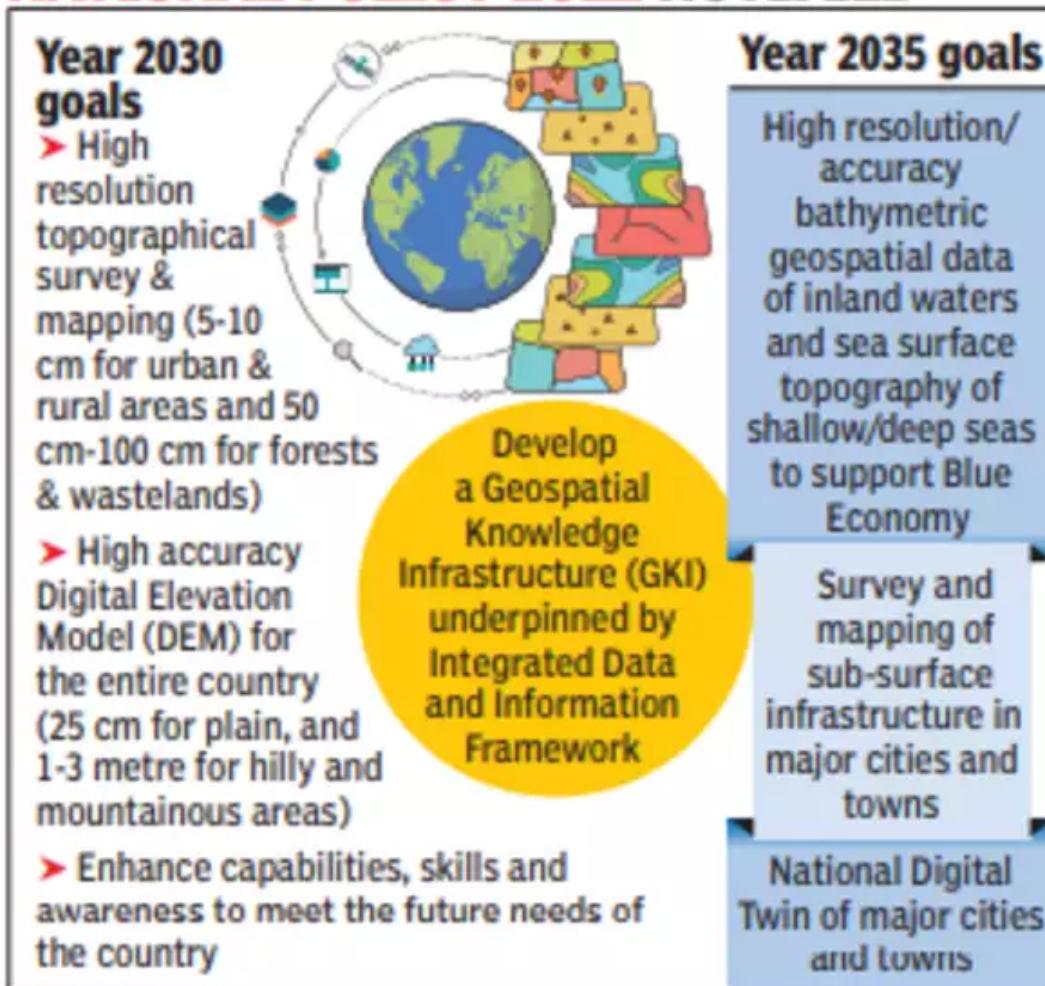
राष्ट्रीय भू-स्थानकि नीति 2022, इसका महत्व और संबंधित चिताएँ

### चर्चा में क्यों?

भारत को वैश्वकि भू-स्थानकि क्षेत्र में एक वैश्वकि नेतृत्वकरत्ता के रूप में स्थापति करने के उद्देश्य सेवजिज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू-स्थानकि नीति (NGP) 2022 की घोषणा की है।

- वर्ष 2025 तक 12.8% की वकास दर से भारत की भू-स्थानकि अरथवयवस्था के 63,000 करोड़ रुपए के आँकड़े को पार करने के साथ ही इसकी सहायता से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किये जाने की उम्मीद है।

# NATIONAL POLICY 2022 NOTIFIED



## पृष्ठभूमि:

- वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में मानचित्र सहित भू-स्थानकि डेटा एकत्र करने और उनकी प्रस्तुति के संबंध में दशा-निर्देश जारी किये गए थे।
- जबकि दशा-निर्देशों ने भू-स्थानकि डेटा एकत्रीकरण/उत्पादन/पहुँच को उदार बनाकर भू-स्थानकि कषेत्र को नियंत्रण मुक्त कर दिया है, नीति 2022 भू-स्थानकि पारतितर के व्यापक विकास के लिये एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

## राष्ट्रीय भू-स्थानकि नीति 2022:

- परचियः**
  - यह भू-स्थानकि प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नागरिक-केंद्रित नीति है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, आरथिक समृद्धि और एक संपन्न सूचना अर्थव्यवस्था को संवरद्धित करने के लिये भू-स्थानकि कषेत्र को मजबूत करना है।
  - इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्च सटीकता वाले डिजिटल एलिविशन मॉडल (DEM) के साथ उच्च रजिल्यूशन स्थलाकृति के सर्वेक्षण और मानचित्रण सुनिश्चित करना है।
- लक्ष्य एवं उद्देश्यः**
  - यह उच्च स्तरीय नवाचार पारतितर के साथ भारत को एक वैश्वकि भू-स्थानकि नेता के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
  - एक मजबूत राष्ट्रीय ढाँचे का निर्माण करना, जिसका उपयोग देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने और सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर वितरण के लिये कर सकता है।
  - भू-स्थानकि अवसंरचना, भू-स्थानकि कौशल और ज्ञान, मानक, भू-स्थानकि व्यवसाय विकासित करना।
  - भू-स्थानकि सूचना के सृजन और प्रबंधन हेतु नवाचार को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना।
- संस्थागत ढाँचा:**
  - राष्ट्रीय स्तर पर भू-स्थानकि डेटा संवरद्धन और विकास समिति (Geospatial Data Promotion and Development Committee- GDPDC) भू-स्थानकि कषेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित रणनीतियों को तैयार करने एवं लागू करने हेतु शीर्ष नियम होगी।
  - वर्ष 2021 में गठित GDPDC वर्ष 2006 में गठित राष्ट्रीय स्थानकि डेटा समिति (National Spatial Data Committee- NSDC)

- को प्रत्यसिथापति और इसके कार्यों एवं शक्तयों को समाहति करेगा।
- बज़िज़ान और प्रौद्योगिकी वभिग सरकार का नोडल वभिग बना रहेगा तथा GDPDC भू-स्थानकि प्रशासन से संबंधति अपने कार्यों के नरिवहन में DST को उपयुक्त सफिरशिं करेगा।
- वज़िन को साकार करने हेतु नीतिगत नरिण्य:

  - वर्ष 2025:
    - भू-स्थानकि क्षेत्रों के उदारीकरण और मूल्यवरद्धति सेवाओं के साथ संवरद्धति व्यावसायीकरण के लयि डेटा के लोकतंत्रीकरण का समर्थन करने वाली एक सक्षम नीति एवं कानूनी ढाँचा तैयार कया जाए।
  - वर्ष 2030:
    - उच्च वभिदन स्थलाकृतकि सर्वेक्षण और मानचतिरण (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लयि 5-10 सेमी. एवं जंगलों व बंजर भूमि हेतु 50-100 सेमी.)।
  - वर्ष 2035:
    - बलू इकॉनमी का समर्थन करने के लयि उच्च वभिदन/सटीकता युक्त अंतरदेशीय जल और उथले/गहरे समुद्र की सतह स्थलाकृतकि बाथमिटरकि भू-स्थानकि डेटा।
    - प्रमुख शहरों और कस्बों का नेशनल डजिटिल ट्वनि (Twin)। डजिटिल ट्वनि एक भौतकि संपतति, प्रक्रया या सेवा की एक आभासी प्रतिकृति है जो नई डजिटिल करांति के केंद्र में है।
      - नेशनल डजिटिल ट्वनि (Twin) स्मार्ट, डायनेमिक, कनेक्टेड डजिटिल ट्वनिस का एक इकोसिस्टम होगा, जो बेहतर नरिण्य लेने की सुवधा के लयि सुरक्षति और इंटरऑपरेबल (Interoperable) डेटा शेयरगि द्वारा सक्षम होगा।

- महत्वतः:
  - भू-स्थानकि प्रौद्योगिकी और डेटा सतत वकिस लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लयि परविरतन एजेंटों के रूप में कार्य कर सकते हैं।
  - यह स्टार्टअप को बढ़ावा देने और बाह्य देशों पर नरिभरता को कम करने के लयि एक जीवंत पहल है।
  - सैन्य संचालन, आपदा और आपातकालीन प्रबंधन, प्रयावरण नगिरानी, भूमि एवं शहर के लयि योजना जैसेमहत्वपूरण डेटा प्रबंधन अनुप्रयोगों हेतु भू-स्थानकि डेटा आवृत्तयों के व्यापक स्पेक्ट्रम में महत्वपूरण भूमिका नभिते हैं।

## संबंधति चतिाएँ:

- जटलि डेटा:
  - भू-स्थानकि डेटा को जटलि संबंधों वाले डेटा विषय के रूप में उनके मध्य वरणति कया जा सकता है।
  - ऐसा डेटा जसि अभी पूरी तरह से समझा और संबोधति कया जाना बाकी है, को सुरक्षति रखने में बड़ी चुनौतयाँ और अड़चनें आती हैं।
- सुरक्षा चतिाएँ:
  - हालांकि भू-स्थानकि डेटा तक पहुँच को प्रबंधति करने और साझा करने के लयि कई प्रकार के मॉडल एवं तकनीकें उपलब्ध हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा चतिआओं को दूर करने पर बहुत कम ध्यान दया गया है, जैसे- पहुँच नयिंत्रण (Access Control), प्रतभूतयों तथा गोपनीय नीतयाँ एवं वशीष रूप से रक्षा क्षेत्र की त्रिसेवाओं (Tri-Services) में सुरक्षति अंतरसंचालनीयता (Interoperable) GIS अनुप्रयोगों का विकास।
- डेटा का दुरुपयोग और गोपनीयता का उल्लंघन:
  - यदि वभिन्न रपिंजिटिरी से डेटा को एकीकृत करके भू-स्थानकि डेटा को पूरे नकिय को उपलब्ध कराया जाएगा, तो संभावति डेटा के दुरुपयोग और गोपनीयता के उल्लंघन की गंभीर संभावनाएँ हैं।
  - रक्षा अनुप्रयोगों के संदर्भ में एक प्रमुख चतिए का विषय यह है कि "स्वामित्व नरिमाण जैसी संवेदनशील जानकारी भी प्रकट हो सकती है या महत्वपूरण बुनियादी ढाँचे के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से सुलभ हो सकती है।

## भू-स्थानकि प्रौद्योगिकी:

- भू-स्थानकि प्रौद्योगिकी में भौगोलिक मानचतिरण और विश्लेषण हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System-GIS), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning System- GPS) और रमिट सेंसरि जैसे उपकरणों का उपयोग कया जाता है।
- ये उपकरण वस्तुओं, घटनाओं और प्रघटनाओं (पृथकी पर उनकी भौगोलिक स्थितिकि अनुसार अनुक्रमति जयिटैग) के बारे में स्थानकि जानकारी प्रदान करते हैं। कसी स्थान का डेटा स्थिरि (Static) या गतशील (Dynamic) हो सकता है।
- कसी स्थान के स्थिरि डेटा/स्टेटकि लोकेशन डेटा (Static Location Data) में सडक की स्थिति, भूकंप की घटना या कसी वशीष क्षेत्र में बच्चों में कुपोषण की स्थितिकि बारे में जानकारी शामलि होती है, जबकि कसी स्थान के गतशील डेटा/डायनेमिक लोकेशन डेटा (Dynamic Location Data) में संचालति वाहन या पैदल यात्री, संक्रामक बीमारी के प्रसार आदि से संबंधति डेटा शामलि होता है।
- बड़ी मात्रा में डेटा में स्थानकि प्रतरिपृष्ठ की पहचान के लयि इंटेलजिंस मैप्स (Intelligent Maps) नरिमति करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग कया जा सकता है।
- यह प्रौद्योगिकी दुर्लभ संसाधनों के महत्व और उनकी प्राथमिकता के आधार पर नरिण्य लेने में मददगार हो सकती है।

## आगे की राह

- आपदा नियोजन परिवृश्य में भाग लेने वाले व्यक्तियों और संगठनों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिये लागू किया जाना चाहयि किउपयोगकरताओं एवं एप्स के पास केवल उसी डेटा तक पहुँच हो जिसकी उनहें आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय भू-स्थानकि नीति 2022 में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्वरों हेतु सुरक्षित एक स्पष्ट रोडमैप और SOP तैयार किया जाना चाहयि, चाहे वह तीनों सैन्य सेवा, अर्द्धसैनिक या महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा क्षेत्र हों।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

**प्रश्न.** नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया' योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा किंचीन ने किया।
2. एक नीतिगत ढाँचे की स्थापना जसिसे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके किंवे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुवधा प्रदान करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

**स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस**

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-geospatial-policy-2022>